Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश

सितम्बर 2022

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश **3**

- उत्तर प्रदेश बाजरा उत्पादन में दूसरे स्थान पर 3
- सिंचाई के लिये नाली के पानी का इस्तेमाल करेगी उत्तर प्रदेश सरकार 3
- देवरिया के खुर्शीद अहमद 'राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार' से सम्मानित 4
- अब यूरोप और मिडिल ईस्ट तक महकेगा कन्नौज का इत्र 4
- लंपी वायरस: मलेशिया की तर्ज़ पर तीन सौ कि.मी. लंबी इम्यून बेल्ट बनेगी 5
- एससी वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं में आय सीमा समाप्त 6
- प्रदेश में खुलेंगे नौ नए डेयरी संयंत्र 6
- प्रधानमंत्री ने ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया 7
- उत्तर प्रदेश में बनेंगे 18 नए थाने और 22 पुलिस चौकियाँ, कुशीनगर में खुलेगा पर्यटन थाना 8
- उत्तर प्रदेश के पहले तैरते सोलर संयंत्र से विद्युत उत्पादन शुरू 8
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर का शिलान्यास 9
- मुरादाबाद मंडल में बनेगा नंदी अभयारण्य 9
- उन्नाव के नवाबगंज में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव 10
- मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की आयु में हुआ निधन 11
- गोरखपुर के गोविंद मुक्केबाज़ी की एशियन चैंपियनशिप का करेंगे प्रतिनिधित्व 11
- उत्तर प्रदेश के छह ज़िलों में खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज 11
- उत्तर प्रदेश विधानसभा से CRPC संशोधन विधेयक पास 12
- देश की 75 अग्रणी महिलाओं में डॉ. जयदीप और डॉ. नीहारिका, ब्रिटिश उच्चायुक्त ने किया सम्मानित 12
- ग्लोबल हुरुन रिचलिस्ट में शुमार हुआ अलख पांडेय फिजिक्सवाला का नाम 13
- प्रयागराज में देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट तैयार 13
- 'राज्य योजना आयोग' हुआ अब 'राज्य परिवर्तन आयोग' 14
- जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने में मदद करने के लिये नई जैव-ऊर्जा नीति 15
- उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 15
- यूपी के 12 सर्वश्रेष्ठ नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेज अब दूसरे कॉलेजों का करेंगे मार्गदर्शन 16
- उत्तर प्रदेश में एमएसएमई नीति-2022 लागू 16
- उत्तर प्रदेश के चार और शहरों में मेट्रो चलाने की तैयारी 17

नोट :

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश बाजरा उत्पादन में दूसरे स्थान पर

चर्चा में क्यों ?

2 सितंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश बाजरा के उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है। राज्य में लगभग 50 लाख मीट्रिक टन बाजरा का उत्पादन होता है, जो देश में कुल बाजरा उत्पादन का 19.69 प्रतिशत है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने भारत के प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है।
- उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में बाजरा और अन्य पोषक-अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिये कई कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 की कार्य योजना अन्य के साथ-साथ उत्पादन, खपत, निर्यात और ब्रांडिंग को बढ़ाने की रणनीतियों पर केंद्रित है।
- प्रस्तावित कार्य योजना में सरकार बाजरा के खेती क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान देगी। बाजरे की खेती का रकबा, जो 2022 में 9.80 लाख हेक्टेयर था, उसे बढ़ाकर 10.19 लाख हेक्टेयर कर दिया जाएगा। उत्पादकता वर्तमान 24.55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 25.53 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की जाएगी।
- इसी तरह सरकार का लक्ष्य ज्वार की खेती का रकबा मौजूदा 2.15 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 2.24 लाख हेक्टेयर करना है। इसी प्रकार कोदो एवं संवा के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता में भी वृद्धि होगी।
- बाजरे के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये सरकार क्लस्टर प्रदर्शन, साझा बीज वितरण के माध्यम से क्षेत्र विस्तार और मुफ्त बीज मिनीकिट वितरण आयोजित करने की योजना बना रही है।
- बाजरा पानी की कमी और सूखे की स्थिति के लिये सबसे उपयुक्त है। ये अन्य फसलों की तुलना में कम-से-कम 70 प्रतिशत कम पानी की खपत करता है और इसे न्यूनतम इनपुट और लगभग कोई कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती है। किसानों के लिये, बाजरा जलवायु परिवर्तन हेतु कम जोखिम वाली फसल है। इसलिये, सरकार की योजना वर्षा सिंचित क्षेत्रों में पौष्टिक अनाज की खेती को बढ़ावा देने की है।
- इसके अलावा, सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मोटे अनाज को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। सरकार फसल पद्धति आधारित प्रशिक्षण में मोटे अनाज की पूरी जानकारी भी देगी। प्रोटीन, ज़िंक, आयरन और विटामिन सहित विशेष पोषक तत्त्वों से भरपूर किस्मों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिये रोड शो, होर्डिंग, वॉल पेंटिंग आदि के माध्यम से जानकारी का प्रसार किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य, ज़िला और ब्लॉक स्तर पर भी राष्ट्रीय मोटे अनाज दिवस का आयोजन किया जाएगा।
- उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय और वैश्विक बाज़ार के लिये न केवल बाजरा, बल्कि संसाधित, बाजरा उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित और बढ़ावा देगी। बिस्किट फैक्ट्री, ब्रेड फैक्ट्री सहित अन्य खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएंगी।

सिंचाई के लिये नाली के पानी का इस्तेमाल करेगी उत्तर प्रदेश सरकार

चर्चा में क्यों ?

3 सितंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अधिकारियों को प्रदेश में फसलों की सिंचाई के लिये नाली के पानी का उपयोग करने की योजना तैयार करने के निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु

- जल शक्ति मंत्री ने यह सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया कि नाली का पानी नदियों में न गिरे और इसका उपयोग सिंचाई के लिये किया जाए।
- उन्होंने कहा कि इससे नदियों में प्रदूषण नहीं बढ़ेगा और साथ ही सिंचाई की लागत में भी काफी कमी आएगी। इससे सिंचाई में इस्तेमाल होने वाले पानी का संरक्षण करने में भी मदद मिलेगी।
- राज्य में बहने वाले 848 नालों की निगरानी के लिये अधिकारियों को निर्देश देते हुए मंत्री ने कहा कि नालों की निगरानी के लिये 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाए। नालों के आसपास रहने वाले और समाज से जुड़े लोगों को समिति का सदस्य बनाया जाए।
- उन्होंने कहा कि नमामि गंगे विभाग राज्य भर में चल रहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के कार्यों को भी देखेगा।
- नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने इंजीनियरों को निर्देश देते हुए कहा कि वे इस महीने से गंगा की ज़मीन पर सीसीटीवी सर्विलांस लागू करें और कंट्रोल रूम से हर एसटीपी की 24 घंटे निगरानी करें।

देवरिया के खुर्शीद अहमद 'राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार' से सम्मानित

चर्चा में क्यों?

5 सितंबर, 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले के शिक्षक खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2022 से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि इस वर्ष देश भर से 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिये चुना गया था, जिनमें उत्तर प्रदेश से एकमात्र शिक्षक खुर्शीद अहमद भी शामिल थे।
- राष्ट्रपति द्वारा खुर्शीद अहमद को सम्मानस्वरूप रजत पदक, 50 हज़ार रुपए की पुरस्कार राशि का चेक और प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।
- देवरिया में कंपोजिट स्कूल सहवा के खुर्शीद अहमद को यह पुरस्कार विज्ञान शिक्षा में नवाचार के लिये दिया गया है। प्रदेश के बेसिक व माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों में अकेले इनका चयन हुआ है।
- गौरतलब है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रतिवर्ष 5 सितंबर को एक राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करता है, जिसमें देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।
- पुरस्कारों के लिये शिक्षकों का चयन ऑनलाइन तीनस्तरीय चयन प्रक्रिया के ज़रिये पारदर्शी तरीके से किया जाता है।
- शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य देश के शिक्षकों के अनूठे योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता व परिश्रम से न सिर्फ स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है।

अब यूरोप और मिडिल ईस्ट तक महकेगा कन्नौज का इत्र

चर्चा में क्यों?

6 सितंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि एक ज़िला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के तहत कन्नौज के इत्र को वैश्विक बाज़ार में स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार अगले साल फरवरी में पहली बार इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल की मेज़बानी करेगी, जिसमें इत्र उद्योग में अग्रणी फ्राँस समेत यूरोप और मिडिल ईस्ट समेत तमाम अग्रणी देशों के प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल में विभिन्न देशों के आगंतुकों को कन्नौज के इत्र के निर्माण की प्रक्रिया, इसमें इस्तेमाल होने वाले मूल इनग्रेडिएंट्स समेत अन्य खूबियों से परिचित कराया जाएगा।

- यह फेस्टिवल कन्नौज के इत्र निर्माताओं और उद्यमियों को विदेशी कंपनियों के साथ व्यापार के लिये मंच उपलब्ध कराएगा। इसके ज़रिये कन्नौज के इत्र कारोबारियों को भी अपने उत्पादों को विदेशी खरीदारों के सामने प्रदर्शित करने व वैश्विक व्यापार की संभावनाओं को टटोलने का मौका मिलेगा।
- जानकारी के मुताबिक, इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल के लिये विदेशी प्रतिनिधिमंडल को लाने की ज़िम्मेदारी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) की होगी।
- इस आयोजन के तहत लखनऊ में एक दिन का कार्यक्रम होगा, जिसमें विभिन्न सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद सभी विदेशी मेहमानों को कन्नौज ले जाया जाएगा। यहाँ उन्हें इत्र के उद्यमियों, इत्र निर्माताओं व निर्यातकों से मिलने का मौका मिलेगा।
- इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल में दुनिया भर के उन देशों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे, जो इत्र, परफ्यूम से जुड़े उद्योगों से संबंधित हैं। इनमें निर्माता, उद्यमी और विक्रेता सभी शामिल होंगे। खासतौर पर यूरोपीय देश फ्राँस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा दुबई समेत मिडिल ईस्ट के भी कई देश इसमें हिस्सा लेंगे। इन सभी देशों में फ्राँस सबसे अहम है, क्योंकि उसे परफ्यूम इंडस्ट्री में अग्रणी माना जाता है।
- गौरतलब है कि पूरी दुनिया में कन्नौज के इत्र की चर्चा होती है। कन्नौज के इत्र की सबसे खास बात ये है कि यहाँ इत्र के निर्माण में एसेंसियल ऑयल का इस्तेमाल होता है। यह पूरी तरह ऑर्गेनिक होता है और इसके उपयोगकर्त्ता को किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट या नुकसान नहीं होता। वहीं, ज़्यादातर देशों में इत्र या परफ्यूम के निर्माण में एल्कोहल का अधिकाधिक इस्तेमाल होता है। धीरे-धीरे दुनिया का मार्केट एसेंसियल ऑयल की ओर जा रहा है। ऐसे में ये देश भारत की ओर देख रहे हैं।
- इस फेस्टिवल में आने वाले विदेशी मेहमानों को लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर बन रहे इत्र पार्क में भी ले जाया जाएगा। कन्नौज में राज्य सरकार 57 एकड़ के क्षेत्र में इत्र पार्क का निर्माण कर रही है। इसके पहले चरण का उद्घाटन इसी साल नवंबर के अंत तक होने की संभावना है। पहले चरण में 30 एकड़ पर निर्माण होगा, जबकि दूसरे चरण में बाकी 27 एकड़ पर पार्क का निर्माण किया जाएगा।
- इत्र पार्क में कन्नौज के छोटे इत्र कारोबारियों को प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे, जहाँ वो अपने उत्पादों को बड़े स्तर पर प्रदर्शित कर पाएंगे। इस इत्र पार्क के ज़रिये सरकार का उद्देश्य छोटे स्तर पर घरों से या दुकानों से इत्र का काम कर रहे लोगों को एडवांस मशीनरी के साथ सामान्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।

लंपी वायरस: मलेशिया की तर्ज़ पर तीन सौ कि.मी. लंबी इम्यून बेल्ट बनेगी

चर्चा में क्यों ?

8 सितंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश पशुधन विभाग के विशेष सचिव देवेंद्र पांडे ने बताया कि प्रदेश के पश्चिमी ज़िलों में लंपी वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए विभाग ने मलेशिया की तर्ज़ पर पीलीभीत से लेकर इटावा तक लगभग 300 किमी. की दूरी को 10 किमी. चौड़े इम्यून बेल्ट से कवर करने का मास्टर प्लान तैयार किया है।

प्रमुख बिंदु

- विशेष सचिव देवेंद्र पांडे ने बताया कि इस मास्टर प्लान को राज्य सरकार ने स्वीकृत कर लिया है। यह बेल्ट एक तरह से बॉर्डर का काम करेगी और लंपी वायरस इसे पार कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ नहीं जा सकेगा।
- पशुपालन विभाग की ओर से वैक्सीनेशन के ज़रिये इम्यून बेल्ट बनाने की तैयारियाँ पूरी की जा चुकी हैं। इस पूरी बेल्ट में पशुओं में शत-प्रतिशत टीकाकरण किया जाएगा। इस अभियान की निगरानी के लिये विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। टास्क फोर्स लंपी वायरस से संक्रमित पशुओं की ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का ज़िम्मा संभालेगी।
- संक्रमित पशुओं की कड़ी निगरानी रखने के साथ ही इन्हें इम्यून बेल्ट के भीतर ही रोकने की व्यवस्था होगी। दरअसल पशुओं के संक्रमण को रोकने के लिये ऐसा प्रयास वर्ष 2020 में मलेशिया में किया जा चुका है, जिसके परिणाम काफी सकारात्मक आए थे।
- मलेशिया की तर्ज पर बनने वाली यह बेल्ट पाँच ज़िलों के 23 ब्लॉकों से होकर गुज़रेगी। इम्यून बेल्ट पीलीभीत ज़िले के बीसलपुर, बरखेड़ा, ललोरीखेड़ा, मरोरी और अमरिया विकास खंड से होते हुए शाहजहाँपुर ज़िले के खुदागंज, निगोही, सिधौली, भावल खेड़ा, कांट, जलालाबाद और मिर्ज़ापुर विकास खंड के रास्ते फर्रुखाबाद ज़िले के कायमगंज, शमसाबाद और राजेपुर विकासखंड होते हुए मैनपुरी ज़िले के कुरावली, सुल्तानगंज और घिरौर विकास खंड तथा इटावा के बढ़पुरा, जसवंतनगर, सैफई, बसरेहर और ताखा विकासखंड तक जाएगी।

- प्रदेश में लंपी वायरस के ज़्यादातर मामले पश्चिमी ज़िलों में ही सामने आए हैं। प्रदेश के 23 ज़िले लंपी वायरस से प्रभावित हैं। इनमें अलीगढ़, मुज़फ्फरनगर और सहारनपुर में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं मथुरा, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मेरठ, शामली और बिजनौर में भी वायरस तेज़ी से पाँव पसार रहा है।
- लंपी वायरस के कारण अब तक प्रदेश के 2,331 गाँवों के 21,619 गोवंश संक्रमित हो चुके हैं। संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू किया है तथा अब तक 5,83,600 गोवंश का टीकाकरण हो चुका है।
- उल्लेखनीय है कि लंपी वायरस पशुओं में पाया जाने वाला एक खतरनाक वायरस है। यह मक्खियों और मच्छरों की कुछ प्रजातियों और कीटों द्वारा एक पशु के शरीर से दूसरे पशु के शरीर तक यात्रा करता है। लंपी वायरस से संक्रमित पशुओं को तेज़ बुखार आने के साथ ही उनकी भूख कम हो जाती है। इसके अलावा चेहरे, गर्दन, थूथन, पलकों समेत पूरे शरीर में गोल उभरी हुई गांठें बन जाती हैं। साथ ही पैरों में सूजन, लंगड़ापन और नर पशु में काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है। कई बार पशुओं की मौत भी हो जाती है।

एससी वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं में आय सीमा समाप्त

चर्चा में क्यों ?

11 सितंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (अनुगम) के चेयरमैन डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने बताया कि अनुगम की स्वरोज़गार योजनाओं का लाभ लेने के लिये अधिकतम आय सीमा की शर्त को खत्म कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- चेयरमैन डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने बताया कि अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ ले सकेगा, लेकिन ढाई लाख रुपए तक सालाना आय वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- स्वरोज़गार की इकाई समूह में स्थापित करनी होगी और अनुदान की सीमा भी प्रति लाभार्थी 10 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 50 हज़ार रुपए कर दी गई है। उत्तर प्रदेश अनुगम की योजनाओं में पात्रता के लिये अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में 47,080 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपए वार्षिक आय सीमा थी।
- गौरतलब है कि जुलाई 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आय और अनुदान सीमा में वृद्धि के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया था। इसी के तहत केंद्र सरकार ने पात्रता के लिये आय सीमा और अनुदान राशि में बड़ा बदलाव किया है।
- चेयरमैन ने बताया कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाएँ अब 'प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना' के नाम से जानी जाएंगी। केंद्र व प्रदेश सरकार ने दलित दंश समाप्त करने के लिये महत्त्वाकांक्षी योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर पहुँचाकर दलितों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिये यह बड़ा कदम उठाया है।
- डॉ. निर्मल ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति बहुल गाँवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना संचालित होगी। इसके तहत व्यक्तिपरक परियोजनाओं की जगह दलितों के समूहों को उद्यमी बनाया जाएगा। लाभार्थियों को प्रोजेक्ट बनाने के लिये प्रशिक्षण दिलाने व उनके उद्यम पर निगरानी की व्यवस्था की गई है।
- लाभार्थियों के उत्पादों को बाज़ार उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है। प्रदेश में 6171 अनुसूचित जाति बहुल गाँवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किये जाने की योजना बनाई गई है।

प्रदेश में खुलेंगे नौ नए डेयरी संयंत्र

चर्चा में क्यों ?

12 सितंबर, 2022 को ग्रेटर नोएडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 (IDF World Dairy Summit 2022) के उद्घाटन सत्र में अपने भाषण के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य देश का शीर्ष दूध उत्पादक है और अगले दो वर्षों में नौ नए डेयरी संयंत्र काम करने लगेंगे।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह सम्मेलन इससे पहले भारत में 1974 में आयोजित किया गया था।
- चार दिन तक चलने वाले इस डेयरी सम्मेलन में भारत सहित दुनिया भर के डेयरी से जुड़े लोग हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा कार्यक्रम में उद्योग जगत के लीडर, विशेषज्ञ, किसान और नीति निर्माता भी हिस्सा लेंगे।
- यह सम्मेलन 'पोषण और आजीविका के लिये डेयरी' विषय पर केंद्रित है। इसके अलावा यह रोज़गार सृजन और पोषण पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जो काफी प्रासंगिक मुद्दे हैं।
- योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश 319 लाख टन वार्षिक दूध उत्पादन के साथ देश के कुल डेयरी उत्पादन में 16 प्रतिशत का योगदान देता है और देश का शीर्ष दूध उत्पादक राज्य है।
- उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अभी संगठित क्षेत्र में 110 डेयरियाँ काम कर रही हैं और इसमें सहकारी क्षेत्र की डेयरियाँ भी शामिल हैं। प्रदेश में 8,600 दुग्ध समितियाँ भी हैं, जिनके जरिये दूध उत्पादन में लगे चार लाख से अधिक सदस्य सक्रिय हैं।
- उन्होंने कहा कि इस समय उत्तर प्रदेश में नए ग्रीनफील्ड डेयरी संयंत्र शुरू करने के लिये काम तेजी से चल रहा है। ये संयंत्र अगले एक से दो साल में चालू हो जाएंगे। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी ही चार और दुग्ध उत्पादक संस्थाओं की स्थापना करने के लिये काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगले पाँच वर्षों के दौरान नंद बाबा दूध मिशन के तहत राज्य में निवेश करेगी।

प्रधानमंत्री ने ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों ?

12 सितंबर, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 IDF World Dairy Summit 2022) का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- 12 से 15 सितंबर तक आयोजित चार-दिवसीय आईडीएफ डब्ल्यूडीएस 2022, 'डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड' के विषय पर केंद्रित उद्योग जगत के दिग्गजों, विशेषज्ञों, किसानों और नीति योजनाकारों सहित वैश्विक व भारतीय डेयरी हितधारकों का एक समूह है।
- आईडीएफ डब्ल्यूडीएस 2022 में 50 देशों के लगभग 1500 प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है। इस तरह का पिछला शिखर सम्मेलन भारत में लगभग आधी सदी पहले 1974 में आयोजित किया गया था।
- प्रधानमंत्री ने भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य में 'पशु धन' और दूध से संबंधित व्यवसाय के महत्त्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि विश्व के अन्य विकसित देशों से अलग, भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान हैं। भारत के डेयरी सेक्टर की पहचान 'मास प्रोडक्शन' से ज्यादा 'प्रोडक्शन बाय मासेस' की है। एक, दो या तीन मवेशियों वाले इन छोटे किसानों के प्रयासों के आधार पर भारत सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है।
- उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में दूध का उत्पादन 2 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है जबकि भारत में यह 6 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक दर से बढ़ रहा है। यह क्षेत्र देश में 8 करोड़ से अधिक परिवारों को रोज़गार प्रदान करता है।
- सरकार ने डेयरी क्षेत्र की बेहतरी के लिये कई कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप पिछले आठ वर्षों में दूध उत्पादन में 44 फीसदी से अधिक की वृद्धि हुई है।
- भारतीय डेयरी उद्योग अनूठा है, क्योंकि यह एक सहकारी मॉडल पर आधारित है, जो छोटे और सीमांत डेयरी किसानों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाता है।
- भारतीय डेयरी उद्योग की सफलता की कहानी, जो वैश्विक दूध का लगभग 23 प्रतिशत हिस्सा है, सालाना लगभग 210 मिलियन टन का उत्पादन करती है और 8 करोड़ से अधिक डेयरी किसानों को सशक्त बनाती है, को आईडीएफ डब्ल्यूडीएस 2022 में प्रदर्शित किया जाएगा।
- इस शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारतीय डेयरी को मदद मिलेगी साथ ही किसानों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।

उत्तर प्रदेश में बनेंगे 18 नए थाने और 22 पुलिस चौकियाँ, कुशीनगर में खुलेगा पर्यटन थाना

चर्चा में क्यों ?

14 सितंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने बताया कि राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न ज़िलों में पुलिसिंग व्यवस्था को और अधिक मज़बूत बनाने के लिये 18 नए थाने और 22 चौकियाँ बनाने एवं कुशीनगर में नया पर्यटन पुलिस थाना खोलने का फैसला किया है।

प्रमुख बिंदु

- संजय प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में शांति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने, अपराधों पर और अधिक प्रभावी तरीके से अंकुश लगाए जाने, महिलाओं तथा आम लोगों को और अधिक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिये राज्य के विभिन्न ज़िलों में 18 नए थाने और 22 चौकियाँ बनाने का निर्णय लिया गया है।
- इस संबंध में पुलिस महानिदेशक और अपर पुलिस महानिदेशक (पुलिस मुख्यालय) को ज़रूरी आदेश जारी कर दिये गए हैं। इसके अलावा प्रदेश के इन नए थानों और पुलिस चौकियों में ज़रूरी पदों के सृजन के बारे में अलग से निर्देश जारी किये जाएंगे।
- गाज़ियाबाद ज़िले के मसूरी/कविनगर थाने के क्षेत्र को काटकर वेब सिटी के नाम से तथा विजय नगर थाने के क्षेत्र को काटकर क्रासिंग रिपब्लिक नाम से नए थाने बनाए गए हैं। खम्पर और बांकाटा थाने के बँटवारे के बाद देवरिया में सुरोली नया थाना होगा।
- अयोध्या के मवई थाने का क्षेत्र काटकर बाबा बज़ार नाम से नया थाना बनाया गया है। राजधानी लखनऊ के मलीहाबाद थाना क्षेत्र के रहीमाबाद गाँव में स्थापित पुलिस चौकी को उच्चीकृत कर रहीमाबाद नाम से नया थाना बनाया गया है। प्रयागराज के धूमनगंज क्षेत्र में एयरपोर्ट थाने की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- प्रमुख सचिव ने बताया कि अलीगढ़ में पाँच, गाज़ीपुर में तीन और हरदोई तथा सीतापुर में दो-दो नई पुलिस चौकियाँ खोली गई हैं। इसके अलावा फर्रूखाबाद, आगरा, मथुरा, बहराइच, प्रयागराज, हरदोई, अमेठी, सीतापुर, उन्न्नाव, प्रतापगढ़ में एक-एक नई पुलिस चौकी खोली जाएगी।

उत्तर प्रदेश के पहले तैरते सोलर संयंत्र से विद्युत उत्पादन शुरू

चर्चा में क्यों ?

15 सितंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले के दिबियापुर में एनटीपीसी में कई चरणों में हुई जाँच के बाद 20 मेगावाट के तैरते सोलर संयंत्र से बिजली का उत्पादन शुरू हो गया। इससे एनटीपीसी औरैया संयंत्र की कुल क्षमता बढ़कर 704 मेगावाट हो गई है।

प्रमुख बिंदु

- एनटीपीसी के अपर महाप्रबंधक संजय बाल्यान ने बताया कि यह तैरता सोलर संयंत्र प्रदेश में पहला है। एनटीपीसी अब तक चार प्रदेशों- तेलंगाना के रामागुंडम, केरल के कायमकुलम, गुजरात के कवास और आंध्र प्रदेश के सेमाद्री में जलाशय पर तैरते सोलर संयंत्र लगा चुकी है।
- गौरतलब है कि औरैया में फ्लोटिंग सोलर संयंत्र के लिये एनटीपीसी ने सितंबर 2019 में निविदा आमंत्रित की थी। निविदा पाने वाली कंपनी ने जून 2020 में सोलर संयंत्र का काम शुरू किया था। अगस्त 2022 में सोलर प्लांट लगकर तैयार हो गया। इसके बाद टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम पूरा किया गया।
- दिबियापुर स्थित एनटीपीसी में 500 वाट क्षमता के सोलर पैनलों का प्रयोग किया गया है। फ्लोटिंग सोलर संयंत्र की कुल लागत लगभग 90 करोड़ रुपए है।
- एनटीपीसी संयंत्र परिसर में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से 20 मेगावाट क्षमता का ज़मीन पर सोलर संयंत्र लगाया गया। ज़मीन पर लगे सोलर प्लांट में 330 वाट के सोलर पैनल मॉड्यूल लगाए गए हैं। इस संयंत्र से व्यावसायिक बिजली उत्पादन तीन चरणों में (पहले चरण में 10 नवंबर, 2020 को आठ मेगावाट, 4 दिसंबर, 2020 को सात मेगावाट एवं 20 फरवरी, 2021 को पाँच मेगावाट) ग्रिड से जोड़कर शुरू किया जा चुका है।

- अब दिबियापुर फ्लोटिंग सोलर संयंत्र से व्यावसायिक बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। इससे सोलर संयत्र की उत्पादन क्षमता बढ़कर 40 मेगावाट हो गई है। एनटीपीसी औरैया में गैस और नेफ्था से चलने वाला 664 मेगावाट का बिजली उत्पादन संयंत्र भी लगा है। इस प्रकार एनटीपीसी औरैया संयंत्र की कुल क्षमता बढ़कर 704 मेगावाट हो गई है।
- एनटीपीसी अधिकारियों के अनुसार गैस और नेफ्था आधारित संयंत्रों से उत्पादित बिजली पाँच रुपए से लेकर 20 रुपए प्रति यूनिट पड़ती है। सोलर से उत्पादित बिजली 3.02 रुपए प्रति यूनिट पड़ेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर का शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

17 सितंबर, 2022 को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताजनगरी आगरा के फाउंड्री नगर स्थित पीपीडीसी में प्रस्तावित फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर का वर्चुअली शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- 125 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस फ्लैटेड फैक्ट्री प्रोजेक्ट का शिलान्यास नवरात्रि में किया जाना था, लेकिन मुख्यमंत्री ने शिलान्यास कार्यक्रम में तब्दीली करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इसका शिलान्यास किया।
- प्रदेश की इस पहली फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर में एक ही छत के नीचे 200 उद्यमी अपनी फैक्ट्री लगा सकेंगे। 21,500 वर्ग मीटर ज़मीन पर प्रस्तावित फ्लैटेड फैक्ट्री में चार लाख वर्ग फीट का कंस्ट्रक्शन एरिया होगा। पाँच मंजिला भवन में नौ लिफ्ट लगाई जाएंगी।
- उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के उपाध्यक्ष राकेश गर्ग ने बताया कि ईको फ्रेंडली फैक्ट्री परिसर में तीन मेगावाट का सबस्टेशन, बारिश का पानी रोकने और सौर ऊर्जा की व्यवस्था रहेगी। फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में उद्यमी आते ही अपना काम शुरू कर सकता है। यहाँ सिर्फ उसे अपनी मशीनरी लगाकर प्लग ऑन करना है, इसके साथ ही उनका उत्पादन शुरू जाएंगा।
- राकेश गर्ग के अनुसार उद्यमियों को वास्तविक लागत मूल्य पर फैक्ट्री की जगह उपलब्ध कराई जाएगी। गैर-प्रदूषणकारी व्हाइट कैटेगरी में दर्ज उद्योग गारमेंट इंडस्ट्री को प्राथमिकता दी जाएगी, वहीं नए स्टार्टअप भी यहाँ जगह पाएंगे। एक जगह ही गारमेंट की फैक्ट्री होने से आने वाले खरीदारों को एक ही जगह पर सभी ऑर्डर देने की सुविधा मिलेगी। यहाँ डिस्प्ले और सभागार भी बनाया जाएगा।

प्रदेश की पहली फ्लैटेड फैक्ट्री की कुछ महत्त्वपूर्ण बातें-

चार मंजिला परिसर में स्थापित होंगी औद्योगिक इकाइयाँ।
फाउंड्री नगर में प्रस्तावित इमारत 21,500 वर्ग मीटर में होगी।
हर फ्लोर पर एक लाख वर्ग फीट एरिया का उपयोग होगा।
सामान, कर्मचारियों के लिये नौ लिफ्टें लगाई जाएंगी।
भूतल पर उद्योग संबंधी आपूर्ति के लिये सपोर्ट फैसिलिटी एरिया बनेगा।
कर्मचारियों के लिये कैंटीन की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पैनल, एसटीपी बनाया जाएगा।
ज़ीरो डिस्चार्ज कैंपस होगा, बिजली का अलग सबस्टेशन होगा।
परिसर के दोनों ओर 18 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण होगा।
उद्योगों के लिये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ब्लॉक बनाया जाएगा।

मुरादाबाद मंडल में बनेगा नंदी अभयारण्य

चर्चा में क्यों ?

19 सितंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडलायुक्त आन्जनेय सिंह ने बताया कि आवारा पशुओं की समस्या को दूर करने के लिये मुरादाबाद मंडल में नंदी अभयारण्य बनाए जाने की पहल की जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य में गायों के रखरखाव के लिये बड़ी संख्या में गोशालाएँ बनाई गईं हैं तथा उनकी व्यवस्था सुधारी गई है, लेकिन नंदियों की देखभाल का कोई इंतजाम नहीं हो सका। इस समस्या के समाधान के क्रम में इन अभयारण्यों की स्थापना की योजना बनाई गई है।
- मंडलायुक्त ने बताया कि मुरादाबाद मंडल के तीन ज़िलों- संभल, अमरोहा और बिजनौर में इसकी पहल की जा रही है। यहाँ नंदी अभयारण्य की स्थापना का काम शुरू कर दिया गया है।
- इन अभयारण्य में नंदी बिना किसी डर के घूम सकेंगे। इसके लिये फिलहाल यहाँ आसपास करौंदा के पेड़ लगाए जाएंगे। इसके बाद बाँस समेत कई ऐसे पौधे लगाए जाएंगे, जिनसे आमदनी भी होगी।
- नंदी अभयारण्यों की आय के अपने स्रोत होंगे, जिससे इनके संचालन में किसी तरह की समस्या भविष्य में न हो। नंदियों को चरने के लिये चारागाह और घास की व्यवस्था भी होगी।
- तीनों ज़िलों में सफलतापूर्ण संचालन के बाद इस प्रोजेक्ट को राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। सबकुछ ठीक रहा तो भविष्य में इस तरह के अभयारण्य आवारा पशुओं से प्रभावित अन्य ज़िलों में बनाए जा सकेंगे।
- नंदियों को एक स्थान पर लाकर, उनके लिये भयमुक्त वातावरण के साक्षी यह नंदी अभयारण्य बनेंगे। पेड़-पौधों और घास के बीच नंदी विचरण करेंगे। पीने के पानी के लिये अगर कोई जलाशय होगा, उससे भी इन अभयरण्यों को जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही ट्यूबवेल का भी इंतजाम किया जाएगा।
- इसके लिये संबंधित ग्रामसभा के ग्राम प्रधान की सलाह और सहयोग भी इसमें शामिल होगा। अपर आयुक्त बीएन यादव को इस योजना पर मॉनीटरिंग की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
- मंडलायुक्त ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का प्रयोग सफल हो गया तो यह राज्य के सभी ज़िलों में कारगर होगा। इसी मंशा से इसकी शुरुआत की गई है।

उन्नाव के नवाबगंज में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों ?

20 सितंबर, 2022 को कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले के नवाबगंज में जेवर से भी बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- दिल्ली-एनसीआर की तर्ज़ पर लखनऊ-कानपुर राज्य राजधानी क्षेत्र में तीन और शहरों- सीतापुर, रायबरेली तथा हरदोई को भी शामिल किया गया है। इससे पहले लखनऊ और कानपुर के अलावा उन्नाव और बाराबंकी शहर ही शामिल थे।
- केडीए के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट बनने के लिये लगभग 10 हज़ार एकड़ ज़मीन की ज़रूरत होगी। ज़मीन को चिह्नित करने का कार्य शुरू हो गया है।
- अरविंद सिंह ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में लगभग 9 महीने लगे हैं। नवाबगंज के पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना इसलिये भी ज़रूरी है, क्योंकि अमौसी एयरपोर्ट का विस्तार अब और नहीं हो सकता।
- शासन के निर्देश पर केडीए ने राज्य राजधानी क्षेत्र के तहत जो कॉन्सेप्ट प्लान बनाया है, उसमें नवाबगंज पक्षी विहार से एयरपोर्ट की न्यूनतम दूरी 5 किमी. रखी गई है, ताकि पक्षियों के हैबीटेट पर कोई असर न पड़े।
- इस एयरपोर्ट का फायदा न सिर्फ राज्य राजधानी क्षेत्र, बल्कि बुंदेलखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहरों, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश तक के लोगों को मिलेगा।

मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की आयु में हुआ निधन

चर्चा में क्यों ?

21 सितंबर, 2022 को मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के AIIMS अस्पताल में 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दिल्ली एम्स में उनका बीते 41 दिनों से इलाज चल रहा था, जहाँ उन्होंने उपचार के दौरान अंतिम सांस ली।

प्रमुख बिंदु

- राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त को जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते समय दिल का दौरा पड़ने के बाद नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया था। वह तब से लाइफ सपोर्ट पर थे और उनमें सुधार के कुछ लक्षण भी दिखे थे।
- उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में 25 दिसंबर, 1963 को हुआ था। उनका असली नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था, जिन्हें पेशेवर रूप से राजू श्रीवास्तव के नाम से जाना जाता है। राजू श्रीवास्तव को अक्सर 'गजोधर भइया'के नाम से जाना जाता है।
- राजू श्रीवास्तव एक भारतीय हास्य अभिनेता, अभिनेता और राजनीतिज्ञ थे। 2014 से वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। मार्च 2019 में उन्हें उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।
- वे 1980 के दशक में हिन्दी फिल्म उद्योग में काम करने के लिये मुंबई चले गए। उन्होंने बाजीगर, बॉम्बे टू गोवा, आमदनी अठन्नी खरचा रुपैया आदि फिल्मों में अभिनय किया।
- वे कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज'में उपविजेता बने। उन्होंने इसके स्पिन-ऑफ शो 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज-चैंपियंस'में 'द किंग ऑफ कॉमेडी'का खिताब जीता।

गोरखपुर के गोविंद मुक्केबाज़ी की एशियन चैंपियनशिप का करेंगे प्रतिनिधित्व

चर्चा में क्यों ?

22 सितंबर, 2022 को बाक्सिंग कोच सुजीत कुमार गौतम ने बताया कि जार्डन में 30 अक्टूबर से 12 नवंबर तक होने वाली मुक्केबाज़ी की एशियन चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के गोविंद साहनी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश के गोविंद साहनी राज्य के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, जो भारतीय दल में जगह बनाने में सफल रहे। वह 48 किग्रा भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे।
- विदित है कि गोविंद ने अक्टूबर 2021 में सर्बिया में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, पर कोई पदक नहीं जीत पाये थे।
- उल्लेखनीय है कि गोविंद साहनी ने कर्नाटक में पुरुष एलीट राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, थाइलैंड में ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, वियतनाम में ओपन इंटरनेशनल बाक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, कज़ाखस्तान में ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है।
- इसके अलावा फिनलैंड, पोलैंड, रशिया के साथ भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भी पदक हासिल किया है।

उत्तर प्रदेश के छह ज़िलों में खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज

चर्चा में क्यों ?

22 सितंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार ने वायबलिटी गैप फंडिंग (VGF) स्कीम के तहत प्रदेश के छह ज़िलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की सैद्धांतिक सहमति दी है। 'एक ज़िला एक मेडिकल कॉलेज' (One District One Medical College) कार्यक्रम के तहत यह कार्य किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- 'एक ज़िला एक मेडिकल कॉलेज' कार्यक्रम के तहत पीपीपी मोड पर महोबा, मैनपुरी, बागपत, हमीरपुर, हाथरस और कासगंज ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेडिकल कॉलेज संचालन के लिये टेंडर के माध्यम से निवेशकों का चयन किया जाएगा।
- उत्तर प्रदेश में 16 ज़िलों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोले जाने हैं। छह ज़िलों में मेडिकल कॉलेज खोलने में लगभग 1525 करोड़ रुपए खर्च आएगा। केंद्र सरकार इसमें 1012 करोड़ रुपए सब्सिडी देगी। एक कॉलेज को औसतन 160 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी।
- महराजगंज और संभल में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिये निवेशकर्त्ता का चयन कर कार्य शुरू हो गया है। इसके अलावा शामली और मऊ में मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया चल रही है।
- चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि पीपीपी मॉडल पर खुलने वाले मेडिकल कॉलेजों के लिये राज्य सरकार ज़िला अस्पताल और भूमि 33 साल की लीज़ पर देगी। इसके बाद निवेशकर्त्ता मेडिकल कॉलेज वापस कर देगा। वह राज्य सरकार की संपत्ति होगी। साथ ही स्टांप ड्यूटी में छूट और उपकरण में सब्सिडी दी जाएगी।
- आलोक कुमार ने बताया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी मिलाकर 65 मेडिकल कॉलेज हैं। केंद्रीय संस्थानों में रायबरेली और गोरखपुर में दो एम्स, एक बीएचयू और एक अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज है।
- प्रदेश के अमेठी, औरैया, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, गोंडा, कानपुर देहात, कौशांबी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, पीलीभीत, सोनभद्र और सुल्तानपुर ज़िले को 2022-23 तक मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। इनका निर्माणकार्य चल रहा है।
- उल्लेखनीय है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल नौ ज़िलों देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाज़ीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया था।

उत्तर प्रदेश विधानसभा से CRPC संशोधन विधेयक पास

चर्चा में क्यों ?

23 सितंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिये CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 बिल पास कर दिया। इसके तहत अब दुष्कर्म व प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेज एक्ट (पॉक्सो) के मामलों में आरोपित को अग्रिम ज़मानत (anticipatory bail) नहीं मिलेगी।

प्रमुख बिंदु

- संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन में दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित करने का प्रस्ताव रखा। विधेयक के पक्ष में सत्ताधारी सदस्यों के बहुमत के कारण विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इसे पारित करने की घोषणा की।
- गौरतलब है कि 22 सितंबर को राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 पेश किया गया था।
- विधेयक के प्रावधान के तहत अब रेप के आरोपियों को अग्रिम ज़मानत नहीं मिलेगी। इस संशोधन विधेयक में CRPC की धारा 438 में बदलाव के साथ ही पॉक्सो एक्ट और 376, 376-A, 376–AB, 376–B, 376-C, 376-D, 376-DA, 376-DB, 386-E की धाराओं में आरोपी को अग्रिम ज़मानत नहीं देने का प्रावधान किया गया है।
- न सिर्फ रेप और गैंगरेप बल्कि यौन अपराध, बदसलूकी और यौन अपशब्द के मामलों में भी अग्रिम ज़मानत नहीं मिल सकेगी।
- हालाँकि, इस कानून को लागू करने पर अभी केंद्र सरकार की मुहर लगना अनिवार्य है क्योंकि इसके लिये गृह मंत्रालय की मंज़ूरी ज़रूरी है।

देश की 75 अग्रणी महिलाओं में डॉ. जयदीप और डॉ. नीहारिका, ब्रिटिश उच्चायुक्त ने किया सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त आवास पर आगरा के रेनबो आईवीएफ और उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल की निदेशक (पूर्व अध्यक्ष, फॉग्सी) डॉ. जयदीप मल्होत्रा और उनकी बेटी डॉ. नीहारिका मल्होत्रा को सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- आज़ादी के अमृत महोत्सव में भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय ने चिकित्सक माँ-बेटी को देश की 75 अग्रणी महिलाओं में स्थान देते हुए पुस्तक 'शी इज वूमेन इन स्टीम'के दूसरे संस्करण में शामिल किया है।
- ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस और भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने उन्हें सम्मानित करने वाली पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक में देश भर की चुनिंदा 75 अग्रणी महिलाओं को स्थान दिया गया है।
- यह पुस्तक इन महिलाओं की वास्तविक जिंदगी की कहानियों, आशा, साहस और दृढ़ संकल्प पर आधारित है। इसमें 75 महिलाओं के साक्षात्कार हैं, जिनमें डॉ. जयदीप मल्होत्रा और डॉ. नीहारिका मल्होत्रा के नाम भी शामिल हैं। दोनों को महिला सशक्तीकरण की मिसाल मानते हुए नि:संतानता के उपचार और समाज में योगदान को देखते हुए सम्मानित किया गया है।
- डॉ. जयदीप मातृ एवं शिशु के स्वास्थ्य पर काम करने वाले डबल्यूएचओ के 125 देशों के समूह फीगो और भारत के एकाउंटेबिलिटी ग्रुप की प्रतिनिधि भी हैं। डॉ. नीहारिका अपनी संस्था 'सेव द गर्ल चाइल्ड' के माध्यम से महिला सशक्तीकरण एवं पर्यावरण पर भी कार्य कर रही हैं।

ग्लोबल हुरुन रिचलिस्ट में शुमार हुआ अलख पांडेय फिजिक्सवाला का नाम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इंटरनेशनल हुरुन रिचलिस्ट में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अलख पांडेय फिजिक्सवाला को स्थान मिला है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 25 रईसों के नाम शामिल हैं। अलख पांडेय का नाम पहली बार इस लिस्ट में शामिल किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि अलख पांडेय की स्टार्टअप कुछ दिन पहले ही 8000 करोड़ रुपए की यूनिकॉर्न लिस्ट में शामिल हुई थी। अलख पांडेय को फिजिक्सवाला के नाम से भी जाना जाता है। वह फिजिक्सवाला के संस्थापक और सीईओ हैं।
- अलख पांडेय को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये जाना जाता है। पढ़ाने के अपने अलग अंदाज़ के लिये वे पूरे देश के छात्रों में लोकप्रिय हैं और उनकी अलग पहचान बन चुकी है।
- अलख पांडेय मूलत: प्रयागराज के रहने वाले हैं। अलख पांडेय की पढ़ाई प्रयागराज से ही विशप जॉनसन स्कूल से हुई थी। उन्हें हाईस्कूल में 91% और 12वीं में 5% अंक मिले थे। उन्होंने स्कूल के समय से ही अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। कुछ समय बाद उन्होंने एक कोचिंग में पढ़ाना शुरू कर दिया।
- साल 2020 में कोरोना के समय लगे लॉक डाउन में नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इसका बहुत लाभ हुआ, साथ ही यूट्यूब चैनल भी काफी लोकप्रिय हुआ। इसी साल अलख पांडेय ने प्रतीक माहेश्वरी के साथ मिलकर फिजिक्सवाला प्राइवेट लिमिटेड के रूप में बतौर कंपनी रजिस्टर कर लिया।

प्रयागराज में देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट तैयार

चर्चा में क्यों ?

25 सितंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार प्रयागराज के फूलपुर में देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट तैयार हो गया है। सरकार की मंजूरी मिलते ही इससे उत्पादन आरंभ हो जाएगा। नवंबर में इस प्लांट के चालू होने की उम्मीद है।

प्रमुख बिंदु

- देश में इफको का फूलपुर स्थित यह दूसरा प्लांट होगा। इफको की देश में पहली नैनो खाद की इकाई गुजरात स्थित कलोल में लगी थी। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया था।

- दूसरे चरण में आँवला (बरेली) और फूलपुर (प्रयागराज) में इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। फूलपुर प्लांट की उत्पादन क्षमता सात करोड़ और आँवला की क्षमता 11 करोड़ बोतल प्रतिवर्ष है।
- फूलपुर में नवंबर से अगले वर्ष मार्च के बीच 70 लाख बोतल खाद उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तीनों प्लांटों से इफको ने सालाना 32 करोड़ बोतल नैनो यूरिया के उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जो 37 करोड़ मीट्रिक टन सब्सिडी वाले यूरिया की जगह लेगा।
- फूलपुर यूनिट के हेड संजय कुदेशिया ने बताया कि प्लांट में नैनो फर्टिलाइजर लिक्विड तैयार किया गया है जिसका नवंबर से उत्पादन आरंभ हो जाएगा। इस खाद से मौजूदा समय में यूरिया के अत्यधिक इस्तेमाल से नष्ट होती उर्वराशक्ति को बचाने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही किसानों का पैसा, परिश्रम और समय भी बचेगा।
- फूलपुर प्लांट में तैयार आधा लीटर नैनो खाद की उर्वरक क्षमता यूरिया की 45 किग्रा. वजनी एक बोरी के बराबर होगी। इसकी आपूर्ति के लिये अर्जेंटीना और ब्राज़ील ने भी इफको से करार किया है।
- फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिये यूरिया के अत्यधिक इस्तेमाल से कृषि भूमि की उर्वरा शत्ति नष्ट होने की शिकायतें लंबे समय से आती रही हैं। इस चिंता को दूर करने के लिये के लिये इफको ने न सिर्फ नैनो फर्टिलाइजर लिक्विड तैयार किया, बल्कि इसका पेटेंट भी कराया है। इफको प्रबंधन का दावा है कि नैनो फर्टिलाइजर से भूमि की उर्वरा शक्ति ही नहीं, उत्पादन भी बढ़ेगा।
- किसानों के लिये यह खाद यूरिया से सस्ती होगी। 45 किग्रा. वाली एक बोरी यूरिया जहाँ 267 रुपए में मिलती है, वहीं इसी ज़रूरत की पूर्ति वाली आधा लीटर लिक्विड नैनो खाद की बोतल 240 रुपए में ही मिल जाएगी। यही नहीं, सरकारी कोष से किसानों को सब्सिडी के रूप में प्रतिवर्ष दिये जाने वाले 24 हज़ार करोड़ रुपए भी बचाए जा सकेंगे।
- गौरतलब है कि नैनो यूरिया पर्यावरण के अनुकूल तो है ही साथ ही यह यूरिया के मुकाबले अधिक लाभदायक भी है। यूरिया से जहाँ फसल को 30 फीसदी लाभ होता है वहीं नैनो यूरिया (नैनो खाद) से फसल को 80 फीसदी लाभ मिलता है। इसके अलावा यूरिया की अपेक्षा नैनो यूरिया का खर्च भी कम है। ड्रोन से भी नैनो खाद का छिड़काव किया जा सकता है।

'राज्य योजना आयोग' हुआ अब 'राज्य परिवर्तन आयोग'

चर्चा में क्यों ?

27 सितंबर, 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यानात्थ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन करते हुए इसका नाम बदलकर राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि राज्य परिवर्तन आयोग (एसटीसी) का नेतृत्व मुख्यमंत्री करेंगे जबकि वित्त मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, कृषि मंत्री, समाज कल्याण मंत्री, पंचायती राज विकास मंत्री, औद्योगिक विकास मंत्री, जल शत्ति मंत्री और शहरी विकास मंत्री इसके सदस्य होंगे।
- एसटीसी के उपाध्यक्ष प्रसिद्ध अर्थशास्त्री या सामाजिक वैज्ञानिक होंगे। अन्य सदस्यों में मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त, कृषि, ग्रामीण विकास, चिकित्सा और स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और योजना सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव शामिल हैं।
- आयोग में गैर-सरकारी सदस्य भी होंगे, जो सामाजिक क्षेत्र, कृषि और अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ होंगे। इन मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि यह आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा और विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद नीतियाँ तैयार करेगा। राज्य जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, उनकी आयोग द्वारा पहचान की जाएगी और उनके समाधान के तरीके खोजे जाएंगे। पीपीपी मॉडल के इस्तेमाल पर भी चर्चा की जाएगी। वर्तमान योजना और उनके परिणाम का मूल्यांकन आयोग द्वारा किया जाएगा।
- गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में योजना आयोग की स्थापना 24 अगस्त, 1972 को हुई थी और इसने राज्य सरकार को आवश्यकता आधारित क्षेत्रों की पहचान करके नीतियाँ बनाने में मदद की।

जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने में मदद करने के लिये नई जैव-ऊर्जा नीति

चर्चा में क्यों ?

27 सितंबर, 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यानात्थ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने हेतु एक जैव-ऊर्जा नीति लागू करने का निर्णय लिया गया।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि जैव-ईंधन के उपयोग को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को गति देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है। नई नीति पूर्व की नीतियों की कमियों को दूर कर प्रदेश में जैव ऊर्जा उद्यम स्थापित करने की संभावनाओं को अंतिम रूप देने के लिये बनाई गई है।
- कृषि अपशिष्ट, कृषि उपज बाजार अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट, चीनी मिल अपशिष्ट, शहरी अपशिष्ट और बहुतायत में उपलब्ध अन्य जैविक अपशिष्ट जैव-ईंधन उत्पन्न करने में उपयोग किये जाएंगे।
- जैव-ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम-2018 के अंतर्गत जैव-ऊर्जा उद्यमों को भूमि क्रय पर स्टांप शुल्क में शत-प्रतिशत छूट तथा उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से दस वर्ष तक एसजीएसटी की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति दी गई है।
- नई नीति की अवधि पाँच वर्ष होगी। इस अवधि के दौरान राज्य में स्थापित होने वाली जैव-ऊर्जा परियोजनाओं (संपीड़ित बायोगैस, बायो-कोयला, बायो-एथेनॉल और बायो-डीजल) को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- इस नीति के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन पर 75 लाख रुपए प्रति टन से अधिकतम 20 करोड़ रुपए की दर से सब्सिडी दी जाएगी। बायो-कोयला उत्पादन पर यह सब्सिडी 75,000 रुपए प्रति टन और अधिकतम 20 करोड़ रुपए तथा बायोडीजल के उत्पादन पर 3 लाख रुपए प्रति किलोलीटर होगा।

उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022

चर्चा में क्यों ?

27 सितंबर, 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 को अनुमोदित किया गया। इस नीति में किसी तरह का संशोधन मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही किया जा सकेगा।

प्रमुख बिंदु

- नई नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाले नए एमएसएमई उद्यमों को पूंजीगत उपादान के रूप में 10 प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत तक उपादान उपलब्ध कराया जा सकेगा। पूंजीगत उपादान (छूट) प्लांट व मशीनरी आदि पर निवेश के लिये मिलता है।
- बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में उपादान की यह सीमा 15-25 प्रतिशत तक और मध्यांचल व पश्चिमांचल में 10-20 प्रतिशत तक होगी। एससी-एसटी और महिला उद्यमियों के लिये दो प्रतिशत अधिक छूट दी जाएगी।
- उपादान की अधिकतम सीमा 4 करोड़ रुपए प्रति इकाई निर्धारित की गई है। निवेश पर 25 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी और लिये गए ऋण पर 50 प्रतिशत तक ब्याज में छूट (उपादान) का प्रावधान किया गया है।
- प्रदेश में 10 एकड़ से अधिक के एमएसएमई पार्क स्थापित करने के लिये भूमि खरीदने पर स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी और लिये गए ऋण पर 7 वर्षों तक 50 प्रतिशत ब्याज उपादान (अधिकतम दो करोड़ रुपए) उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, बहिस्राव के निस्तारण के लिये कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान (सीईटीपी) के लिये 10 करोड़ रुपए तक की वित्तीय मदद भी दी जा सकेगी।
- प्रदेश में स्थापित होने वाले नए सूक्ष्म उद्योगों के लिये पूंजीगत ब्याज उपादान के तहत ऋण पर देय वार्षिक ब्याज पर 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। यह ब्याज उपादान 5 वर्षों के लिये दिया जाएगा और अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए प्रति इकाई होगी। एससी-एसटी और महिला उद्यमियों के लिये यह ब्याज उपादान 60 प्रतिशत तक होगा।

- नीति के अनुसार, एमएसएमई इकाइयों को अधिक से अधिक स्रोतों से क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिये स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसी सभी इकाइयों को लिस्टिंग के व्यय का 20 प्रतिशत और अधिकतम 5 लाख रुपए की भरपाई की जाएगी। फ्लैटेड फैक्ट्री की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- औद्योगिक आस्थानों में भूखंडों और शेडों के आवंटन की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई को प्रोत्साहन देने के लिये 5 एकड़ या उससे अधिक ग्राम सभा की भूमि पुनर्ग्रहीत कर निशुल्क उद्योग निदेशालय को स्थानांतरित की जाएगी।
- एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर 5 किमी. की दूरी के अंतर्गत औद्योगिक आस्थानों के विकास के माध्यम से एमएसएमई इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाएगा। परंपरागत औद्योगिक क्लस्टरों में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट की समस्या के मद्देनज़र सीईटीपी को प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान है।
- गुणवत्ता मानक जैसे जीरो इफेक्ट-जीरो डिफेक्ट, डब्ल्यूएचओ जीएमपी, हॉलमार्क आदि प्राप्त करने के लिये कुल लागत का 75 प्रतिशत और अधिकतम 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता तथा जीआई रजिस्ट्रेशन और पेटेंट आदि प्राप्त करने के लिये दो लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलेगी।
- क्लीन एवं ग्रीन तकनीक को अपनाने के लिये एमएसएमई इकाइयों को अधिकतम 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- उद्यमिता विकास संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करते हुए उद्यमिता के पाठ्क्रयमों के आधार पर प्रदेश के युवाओं में उद्यमिता का प्रसार किया जाएगा।

यूपी के 12 सर्वश्रेष्ठ नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेज अब दूसरे कॉलेजों का करेंगे मार्गदर्शन

चर्चा में क्यों ?

28 सितंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मेडिकल एजुकेशन पर फोकस करते हुए राज्य के 12 सर्वश्रेष्ठ नर्सिंग कॉलेजों द्वारा दूसरे कॉलेजों का मार्गदर्शन करने की जानकारी दी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजों में गुणवत्ता सुधार के लिये जल्द 'मिशन निरामया:' शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और रोज़गार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।
- मेंटरशिप के लिये 12 कॉलेजों का चयन किया गया है। इन कॉलेजों को दूसरे कॉलेजों का मेंटर बनाया गया है। गुणवत्तापरक शिक्षा देने और बेहतर प्लेसमेंट दिलाने के लिये इन कॉलेजों द्वारा किये जा रहे बेहतर कार्यों को दूसरे कॉलेजों में भी लागू कराया जाएगा।
- गोरखपुर का जीएसजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी, एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज व आईआईएमटी यूनिवर्सिटी की नर्सिंग फैकल्टी, गौतमबुद्ध नगर के नाइटेंगिल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग व शारदा यूनिवर्सिटी की नर्सिंग फैकल्टी, लखनऊ के बाबा हॉस्पिटल के स्कूल ऑफ नर्सिंग व इटावा की उ.प्र. यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की नर्सिंग फैकल्टी, जीवीएसएम मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग कॉलेज, हिलेरी क्लिंटन स्कूल ऑफ नर्सिंग सहारनपुर और गोंडा व बरेली के नर्सिंग कॉलेज शामिल हैं।
- इन नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजों द्वारा पढ़ाई व प्लेसमेंट के लिये जो भी अच्छे कदम व नव प्रयोग किये जा रहे हैं, वह दूसरे नर्सिंग कॉलेजों में भी लागू कराए जाएंगे।
- नवंबर 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूएसआई) द्वारा 900 नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजों की रेटिंग कराई जाएगी। बिना संसाधन व फैकल्टी के चल रहे नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजों पर ताला जड़ा जाएगा।

उत्तर प्रदेश में एमएसएमई नीति-2022 लागू

चर्चा में क्यों ?

29 सितंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) विभाग ने एमएसएमई नीति-2022 को लागू करने संबंधी शासनादेश जारी कर दिया। यह नीति सितंबर 2027 तक प्रभावी रहेगी।

प्रमुख बिंदु

- एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने बताया कि प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग में निवेश करने वाले उद्यमियों को दो करोड़ रुपए तक के कोलेटरल फ्री ऋण (यानी बिना गिरवी के ऋण) पर बैंकों की ओर से ली जाने वाली वन टाइम गारंटी फीस राज्य सरकार वहन करेगी।
- नए सूक्ष्म उद्योग के लिये ऋण पर देय वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत (अधिकतम 25 लाख रुपए) प्रति इकाई पाँच वर्षों के लिये दिया जाएगा।
- उद्यमियों को पूंजीगत निवेश पर 10 से 25 फीसदी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को ऋण के ब्याज पर 60 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी।
- बुंदेलखंड व पूर्वांचल क्षेत्रों में क्रमश: 25, 20 और 15 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। मध्यांचल एवं पश्चिमांचल में क्रमश: 20, 15 और 10 प्रतिशत होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति व महिला उद्यमियों को 2 प्रतिशत अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन सहायता प्रदान की जाएगी।
- निवेश प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा 4 करोड़ रुपए प्रति इकाई होगी। पाँच करोड़ रुपए और इससे अधिक की मशीनरी एवं संयंत्र वाली सभी नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को कच्चे माल की खरीद पर पाँच वर्ष के लिये मंडी शुल्क से छूट की व्यवस्था मंडी अधिनियम के अनुसार प्रदान की जाएगी। विभाग के औद्योगिक आस्थानों में भूखंडों और शेडों के आवंटन की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा।
- सूक्ष्म इकाइयों के पात्र निवेश के लिये आवेदन अवधि दो वर्ष, लघु उद्योग के लिये तीन वर्ष और मध्यम उद्योग के लिये चार वर्ष होगी।
- प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को अधिक-से-अधिक स्रोतों से क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग पर खर्च के 20 प्रतिशत (अधिकतम 5 लाख रुपए) की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- तंबाकू उत्पादन, गुटखा, पान मसाला, अल्कोहल, वातयुक्त पेय पदार्थ, कार्बोनेटेड उत्पाद, पटाखों का विनिर्माण, प्लास्टिक कैरीबैग (40 माइक्रॉन से कम), राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर प्रतिबंधित श्रेणी में वर्गीकृत मोटाई के प्लास्टिक बैग और समय-समय पर प्रतिबंधित श्रेणी सूची में श्रेणीकृत उत्पादों के निवेश प्रस्तावों पर यह नीति लागू नहीं होगी।

उत्तर प्रदेश के चार और शहरों में मेट्रो चलाने की तैयारी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य के चार और शहरों में मेट्रो चलाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये नए सिरे से रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिये गए।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य के मेरठ, बरेली, झाँसी व प्रयागराज में मेट्रो चलाने के लिये उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। इन शहरों में लाइट अथवा नियो मेट्रो चलाई जाएंगी।
- बनारस में मेट्रो की जगह रोप-वे की तैयारी है। यहाँ पर रोपवे का नए सिरे से टेंडर होगा। इसके अलावा गोरखपुर में लाइट मेट्रो परियोजना की मंज़ूरी के लिये केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।
- एनसीआर के साथ लखनऊ, कानपुर, आगरा के बाद अब राज्य के चार और बड़े शहरों में मेट्रो के निर्माण की तैयारी और तेज हो गई है। बरेली, झाँसी, प्रयागराज के लिये पूर्व में स्थानीय स्तर पर खुद ही डीपीआर तैयार कराई गई थी, लेकिन अब यह उपयोगी नहीं है।
- मेरठ, बरेली, झाँसी व प्रयागराज शहरों में मेट्रो की जगह लाइट अथवा नियो मेट्रो की संभावना तलाशी जा रही है। इसलिये शासन ने यहाँ नए सिरे से फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ-साथ डीपीआर भी तैयार कराई जाएगी। इसमें मेरठ को भी शामिल किया गया है।